



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 13-14 जुलाई 2025



NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बेंगलुरु में VTU-VRIF-TCOE उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया।

जुलाई 2025 में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव (M.) सिंधिया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचार और विकास (DoNER) के विभागों को संभाल रहे हैं, ने आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (VTU) के क्षेत्रीय परिसर में VTU-VRIF-TCOE हब एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का उद्घाटन किया।

● यह उत्कृष्टता केंद्र VTU, विश्वेश्वरैया रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन (VRIF) और टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (TCOE) इंडिया के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह केंद्र 1 लाख वर्ग फुट में फैला है और VTU से संबद्ध 218 संस्थानों, 4 लाख से अधिक छात्रों और 20,000+ शोधकर्ताओं को जोड़ता है। यह केंद्र 5G/6G संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी (AR/VR), क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थटेक और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

● 10 जुलाई 2025 को उद्घाटन के दौरान, मंत्री सिंधिया ने बेंगलुरु के एक वैश्विक डीप-टेक केंद्र में परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि भारत के ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता 250 मिलियन से बढ़कर 974 मिलियन से अधिक हो गए हैं, और यह केंद्र "विचारकों, निर्माताओं और नेताओं की एक पीढ़ी" के रूप में काम करेगा, जो भारत को सेवा-आधारित से उत्पाद नवाचार की ओर ले जाएगा।

● यह hub 20 से अधिक स्टार्टअप्स, 30 से अधिक शैक्षणिक साझेदारों और उद्योग जगत के अग्रणी लोगों जैसे किंसाइट टेक्नोलॉजीज, QpiAI और टेलीवर्ज को दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (TSSC) के नेतृत्व में कौशल निर्माण में सहायता प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) उद्घाटन के साथ-साथ, ज्योतिरादित्य माधवराव (M.) सिंधिया ने दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव डॉ. नीरज मित्तल के साथ Bharat 6G गठबंधन (B6GA) की प्रगति समीक्षा की। इस गठबंधन में अब 80 सदस्य संगठन शामिल हैं—30 से ज़्यादा स्टार्टअप, शिक्षा जगत, सार्वजनिक संस्थान और वैश्विक साझेदार—और इसने स्वदेशी रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN), ग्रामीण कनेक्टिविटी, AI-एकीकृत नेटवर्क और कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में स्मार्ट क्रॉस-सेक्टर 6G अनुप्रयोगों जैसे प्रमुख अनुसंधान एवं विकास मोर्चों पर अपडेट साझा किए।

(ii) सिंधिया ने 2030 तक वैश्विक 6G पेटेंट का 10% हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पुष्टि की, और मजबूत नीति समर्थन, अनुसंधान निधि, समय पर स्पेक्ट्रम आवंटन और गठबंधन कार्य समूहों की लगातार निगरानी का आह्वान किया।

(iii) ये पहल भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट (मार्च 2023 में जारी) द्वारा संचालित हैं और आंशिक रूप से दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) द्वारा वित्त पोषित हैं, जिसने 500 करोड़ रुपये के साथ 120 से

अधिक अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिसमें 6जी के लिए 100 प्रस्ताव शामिल हैं, और 180 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। यह एक लचीला और स्वदेशी दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत के शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक-निजी भागीदारों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है।

2. भारत के मराठा सैन्य किलों को UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।



भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है, जब UNESCO ने 11-12 जुलाई, 2025 को पेरिस में आयोजित UNESCO विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान “भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य” को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।

● यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत का 44वां स्थल है और यह मराठा सैन्य रणनीति और स्थापत्य उत्कृष्टता की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है।

● शिलालेख में 12 किलों का एक नेटवर्क शामिल है जो मराठा साम्राज्य के सैन्य दृष्टिकोण को दर्शाता है, मुख्यतः छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान। इनमें रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, सलहेर, लोहागढ़, पन्हाला, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी (सभी महाराष्ट्र में) और तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल हैं। ये किले मुगल

विस्तार और बाद में ब्रिटिश प्रभाव का विरोध करने के लिए पहाड़ियों, तटीय क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित थे।

● मराठा किलों का चयन UNESCO मानदंड (iv) उनकी अनूठी वास्तुकला और मानदंड (vi) मराठा इतिहास एवं संस्कृति से उनके जुड़ाव के आधार पर किया गया था। इन किलों को पहली बार 2021 में UNESCO की संभावित सूची में शामिल किया गया था। बाद में, भारत ने जनवरी 2024 में आधिकारिक रूप से नामांकन प्रस्तुत किया। उसके बाद, ICOMOS (अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद) की एक टीम ने अक्टूबर 2024 में किलों का निरीक्षण किया और उन्हें सूची में शामिल करने की सिफारिश की। अंततः, UNESCO ने जुलाई 2025 में इस सूची को मंजूरी दे दी।

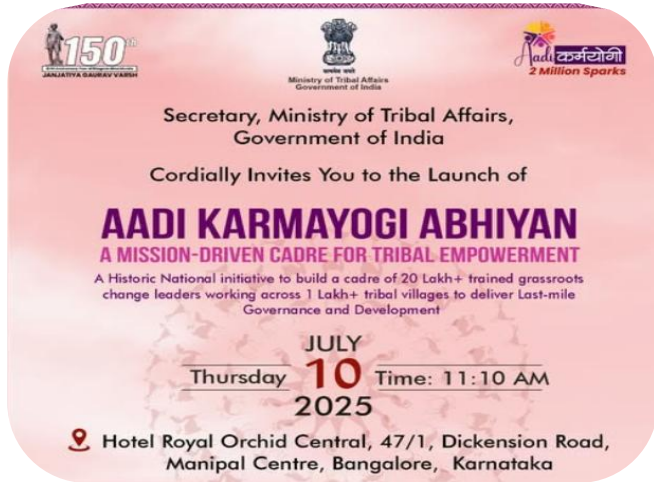
Key Points:-

(i) भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मान्यता का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गौरव का विषय बताया। UNESCO की मान्यता से पर्यटन को बढ़ावा मिलने, रोज़गार सृजन और 12 स्थलों के संरक्षण हेतु धन में वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ii) महाराष्ट्र सरकार ने बफर जोन संरक्षण योजनाओं की घोषणा की है, विशेष रूप से साल्हेर किले के आसपास, जिसमें 10 साल की अवसंरचना और विरासत प्रबंधन योजना शामिल है।

(iii) UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत को विश्व के शीर्ष 6 देशों में और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रखता है। इस मान्यता के साथ, भारत अपनी विविध और बहुस्तरीय ऐतिहासिक पहचान को उजागर करता रहेगा, जिससे UNESCO के वैश्विक विरासत ढाँचे के अंतर्गत भविष्य में सांस्कृतिक नामांकन के लिए उसका दावा मज़बूत होगा।

3. MoTA ने बेंगलुरु में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया लैब लॉन्च की।



जून 2025 में शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख आदिवासी नेतृत्व कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रेरित और नागरिक-केंद्रित आदिवासी अधिकारियों के एक नए कैडर के विकास के माध्यम से आदिवासी कल्याण योजनाओं में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए निचले स्तर से शासन, वास्तविक समय पर शिकायत निवारण और स्थानीय सेवा वितरण पर केंद्रित है।

● बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला (RPL) को पाँच राज्यों: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य मास्टर प्रशिक्षकों (SMTs) को प्रशिक्षित करने हेतु एक क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ये SMTs राज्य प्रक्रिया प्रयोगशालाओं (SPLs) की स्थापना और जिला मास्टर प्रशिक्षकों (DMTs) को आगे प्रशिक्षित करने में मदद करेंगे। इस पहल में जनजातीय क्षेत्रों में वास्तविक समय में सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय समस्या-समाधान और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है।

● जून 2025 में शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख आदिवासी नेतृत्व कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रेरित और नागरिक-केंद्रित आदिवासी अधिकारियों के एक नए कैडर के विकास के माध्यम से आदिवासी कल्याण योजनाओं में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए निचले स्तर से शासन, वास्तविक समय पर शिकायत निवारण और स्थानीय सेवा वितरण पर केंद्रित है।

● यह मिशन जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) सहित प्रमुख मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। यह समावेशी और उत्तरदायी जनजातीय विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप, दूरदर्शिता, सहयोग और जन-प्रथम परिणामों पर आधारित एक शासन मॉडल का समर्थन करता है।

Key Points:-

(i) यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) और DAGUJA (धरतिया आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान) जैसी व्यापक आदिवासी उत्थान योजनाओं के साथ संरेखित है। नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया PM-JANMAN, प्रत्यक्ष आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास को लक्षित करता है।

(ii) अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया DAGUJA (धरती आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान) लगभग 63,000 आदिवासी गांवों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने पर केंद्रित है, जिसमें कुल योजना आवंटन 79,156 करोड़ रुपये है।

(iii) प्रथम क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला के चालू हो जाने के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय का लक्ष्य 20 लाख जनजातीय जमीनी कार्यकर्ताओं और परिवर्तन नेताओं का एक जीवंत नेटवर्क बनाना है, जिससे अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करना, समावेशी विकास और स्थानीय नीति फीडबैक को सक्षम बनाना है, ताकि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जनजातीय सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

4. ऑपरेशन शिवा 2025: भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा के लिए मजबूत सुरक्षा शुरू की।



जुलाई 2025 में, भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा (3 जुलाई - 9 अगस्त, 2025) की सुरक्षा के लिए एक बड़े पैमाने पर, बहुस्तरीय सुरक्षा अभियान "ऑपरेशन शिव 2025" शुरू किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी।

- नुनवान-पहलगाम और बालटाल मार्गों पर 8,500 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। इसके अलावा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) — जिनमें CRPF, BSF, SSB, ITBP और CISF शामिल हैं — के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के लगभग 42,000-50,000 जवान भी तैनात हैं।

- इस अभियान में ड्रोन और IED खतरों का मुकाबला करने के लिए 50 से अधिक मानवरहित

हवाई प्रणालियों (C-UAS), ड्रोन निगरानी, जैमर, उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, बम का पता लगाने वाले दस्ते, खोजी कुत्ते और तोड़फोड़ विरोधी इकाइयों को एकीकृत किया गया है।

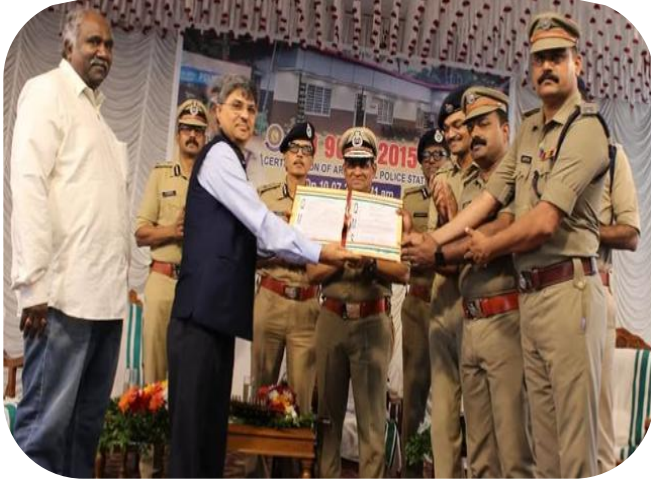
- बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में पुल-बिछाना, ट्रैक संवर्धन, आपातकालीन चिकित्सा सहायता (150 से अधिक डॉक्टर, नौ सहायता चौकियां, 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, 26 ऑक्सीजन बूथ और 2 लाख लीटर ऑक्सीजन), टेंट शहर, जल बिंदु, त्वरित प्रतिक्रिया दल और स्टैंडबाय पर सेना के हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

Key Points:-

(i) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), जम्मू-कश्मीर पुलिस और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के साथ समन्वय से तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए RFID (RFID – रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) ट्रैकिंग कार्ड, बाँडी स्कैनर, CCTV निगरानी, काफिला एस्कॉर्ट, फेसियल रिकग्निशन और एक्स-रे जांच जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा के दौरान अधिकतम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

(ii) ऑपरेशन शिवा 2025 अब तक की सबसे मजबूत अमरनाथ यात्रा सुरक्षा तैनाती का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अत्याधुनिक निगरानी तकनीकें, खतरे से निपटने के लिए खुफिया जानकारी, व्यापक बुनियादी ढाँचे की तैयारी और सैन्य, अर्धसैनिक और नागरिक अधिकारियों के बीच एक मजबूत सुरक्षा सहयोग का इस्तेमाल किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में बढ़ते खतरों के बीच तीर्थयात्री सुरक्षित, निर्बाध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा करें।

5. आर्थिकल पुलिस स्टेशन BIS से ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया।



10 जुलाई, 2025 को केरल के अलप्पुझा जिले में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

- यह प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें स्टेशन की गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग, पेशेवर सेवा वितरण और प्रभावी सार्वजनिक शिकायत तंत्र के अनुपालन को मान्यता दी गई।

- प्रमाणन प्रक्रिया एक संरचित दो-चरणीय ऑडिट के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें जोखिम न्यूनीकरण, नागरिक शिकायत प्रोटोकॉल, बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता और कर्मचारियों की व्यावसायिकता सहित कई गुणवत्ता संकेतकों की जांच की गई।

- इसने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के दिशानिर्देशों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेवा मानकों के प्रति स्टेशन की प्रतिबद्धता को मान्य किया।

Key Points:-

(i) ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र अपराध नियंत्रण,

आपातकालीन प्रतिक्रिया, यातायात नियमन, कानून प्रवर्तन और न्यायिक समन्वय जैसे प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में अर्थनकल पुलिस स्टेशन के प्रदर्शन को भी मान्यता देता है। इन कार्यों का मूल्यांकन कानून-व्यवस्था प्रबंधन और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र पर विशेष जोर देते हुए किया गया।

(ii) इन सुधारों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय और राज्य कानूनी ढाँचों के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सुधार लाना था। अर्थनकल स्टेशन का दृष्टिकोण अद्यतन सरकारी पुलिसिंग निर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप था।

(iii) यह उपलब्धि आधुनिक चेरथला पुलिस कार्यक्रम की व्यापक पहल के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य अलप्पुझा क्षेत्र में पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार और डिजिटलीकरण करना है। इस परियोजना का नेतृत्व सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) हरीश जैन कर रहे हैं, जिन्होंने संरचनात्मक सुधारों, नागरिक संतुष्टि और कानून प्रवर्तन आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक पुलिसिंग प्रोटोकॉल लागू किए हैं।

INTERNATIONAL

1. WTTC वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था सूची 2024 में भारत 8वें स्थान पर, 25 अमेरिका शीर्ष पर।



विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (WTTC) ने अप्रैल 2025 में ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से अपना 2024 आर्थिक प्रभाव अनुसंधान (EIR) जारी किया, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन की हिस्सेदारी के आधार पर 184 देशों की रैंकिंग की गई। भारत 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर आठवें स्थान पर पहुँच गया, जबकि अमेरिका 2.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर बना रहा, जिससे वैश्विक पर्यटन में अमेरिका की प्रमुख भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

● अपनी मज़बूत वैश्विक रैंकिंग के बावजूद, भारत का घरेलू पर्यटन इसकी ताकत बना हुआ है: 2024 में, घरेलू पर्यटकों का खर्च रिकॉर्ड ₹15.5 ट्रिलियन (US\$185.6 बिलियन) तक पहुँच गया, जो 2019 की तुलना में 22% ज़्यादा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का खर्च ₹3.1 ट्रिलियन (US\$36.8 बिलियन) तक पहुँच गया, जो महामारी-पूर्व के स्तर से 9% ज़्यादा है। कुल 2 करोड़ अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों ने भारत का दौरा किया—जो 2019 की तुलना में 23 लाख ज़्यादा है।

Key Points:-

(i) कुल मिलाकर, भारत का यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र 2024 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग ₹20.9 ट्रिलियन (249 अरब अमेरिकी डॉलर) का योगदान देगा, जिससे 4.65 करोड़ नौकरियाँ, यानी कुल रोज़गार का 9.1%, सृजित होंगी। डब्ल्यूटीटीसी का अनुमान है कि 2025 में यह बढ़कर ₹22.5 ट्रिलियन (268.7 अरब अमेरिकी डॉलर) हो जाएगा और 4.8 करोड़ नौकरियाँ पैदा होंगी।

(ii) 2035 तक इस क्षेत्र के लगभग दोगुना होकर 41.9 ट्रिलियन (501 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने और 63.9 मिलियन नौकरियों को समर्थन देने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से घरेलू खर्च वृद्धि से प्रेरित है।

(iii) भविष्य में, WTTC का अनुमान है कि भारत में

अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का खर्च 2025 तक बढ़कर ₹3.2 ट्रिलियन और घरेलू खर्च ₹16 ट्रिलियन हो जाएगा, और 2035 तक इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है (₹32.7 ट्रिलियन घरेलू और ₹4.6 ट्रिलियन अंतरराष्ट्रीय)। इन रुझानों को देखते हुए, भारत के 2035 तक वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुँचने का अनुमान है। WTTC इस विकास क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए पर्यटन अवसंरचना में निरंतर निवेश, सुव्यवस्थित ई-वीज़ा प्रणालियों और निरंतर विदेशी विपणन समर्थन की आवश्यकता पर बल देता है।

2. फोर्ब्स ने 2025 तक अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में भारत को प्रथम स्थान दिया है और जय चौधरी शीर्ष दस अरबपतियों में शामिल हैं।



जुलाई 2025 में, फोर्ब्स ने अपनी "अमेरिका के सबसे अमीर आप्रवासी 2025" रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत दुनिया में सबसे आगे है, जहाँ 12 भारतीय मूल के अरबपति अमेरिका में रहते हैं। यह उपलब्धि भारत को अमेरिका में आप्रवासी धन का शीर्ष स्रोत बनाती है और पिछले अग्रणी इज़राइल को पीछे छोड़ देती है।

● Zscaler के संस्थापक और CEO जय चौधरी इस सूची में सबसे अलग भारतीय हैं—सभी आप्रवासी अरबपतियों में 17.9 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर। हिमाचल प्रदेश के

एक सुदूर गाँव में जन्मे, जहाँ बिजली नहीं थी, चौधरी ने 2007 में Zscaler की स्थापना करने से पहले IIT (BHU) वाराणसी, सिनसिनाटी विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से डिग्री हासिल की।

● जय चौधरी एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी उभरे हैं: 2022 में, उन्होंने उद्यमिता केंद्र और एक सॉफ्टवेयर इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए अपने अल्मा मेटर IIT (BHU) वाराणसी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया, इसके बाद 2023 में शंकर आई फाउंडेशन को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक और उपहार दिया, जो भारत में साध्य अंधेपन को खत्म करने के प्रयासों का समर्थन करता है।

● यह न केवल उनकी व्यावसायिक कुशलता को दर्शाता है, बल्कि अपने मूल देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

Key Points:-

(i) फोर्ब्स की सूची में 43 देशों के कुल 125 विदेशी मूल के अरबपति शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो अमेरिकी अरबपतियों की कुल संपत्ति का 18% है। प्रौद्योगिकी और वित्त क्षेत्र प्रमुख हैं, जहाँ इन अप्रवासी अरबपतियों में क्रमशः 42% और 22% हिस्सेदारी है।

(ii) जय चौधरी के साथ विनोद खोसला (9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर), राकेश गंगवाल (6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर), रोमेश वाधवानी (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर), निकेश अरोड़ा (1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर), सुंदर पिचाई और सत्य नडेला (प्रत्येक 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) जैसे उल्लेखनीय भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जो भारतीय उद्यमशीलता की सफलता की गहराई को उजागर करते हैं - मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, विमानन और वित्त में।

(iii) रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि

आप्रवासी उद्यमी अमेरिकी समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तथा भारतीय मूल के व्यक्ति अब अमेरिका में आप्रवासी धन सृजन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी वृद्धि व्यापक प्रवृत्तियों को रेखांकित करती है - जैसे शीर्ष प्रतिभाओं का वैश्विक प्रवास, साइबरस्पेस में नवाचार, तथा विविध व्यावसायिक समुदायों का आर्थिक प्रभाव।

BANKING & FINANCE

1. कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो ने ब्लूचिप रिवाइस के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पुनः लॉन्च किए।



कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो एयरलाइंस ने अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फिर से लॉन्च किए हैं, जो अब नए लॉन्च किए गए इंडिगो ब्लूचिप लॉयल्टी प्रोग्राम द्वारा संचालित हैं। इस नए ऑफर में एक बेस वेरिएंट और एक प्रीमियम वेरिएंट शामिल है, जिसे रोज़मर्रा के खर्च को यात्रा पुरस्कारों में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आकस्मिक खर्च करने वालों और अक्सर यात्रा करने वालों, दोनों के लिए उपयुक्त हैं।

● दोनों कार्ड उड़ान, भोजन, मनोरंजन और सामान्य खर्चों पर त्वरित कमाई प्रदान करते हैं। ₹3,000+GST के वार्षिक शुल्क वाला यह प्रीमियम कार्ड, इंडिगो बुकिंग पर प्रति ₹100 पर 21 ब्लूचिप्स, भोजन और मनोरंजन पर 3 ब्लूचिप्स, अन्य खर्चों पर

2 ब्लूचिप्स, साथ ही माइलस्टोन बोनस और लाउंज एक्सेस प्रदान करता है।

- बेस कार्ड की कीमत ₹1,500+GST है, जिससे उड़ानों पर ₹100/₹19 की थोड़ी कम छूट मिलती है तथा माइलस्टोन रिवॉर्ड पाने के लिए कम खर्च करना पड़ता है।

Key Points:-

(i) 10 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया यह पुनः लॉन्च, ब्लूचिप को एक वैश्विक यात्रा लॉयल्टी इंजन के रूप में स्थापित करने के इंडिगो के व्यापक मिशन के अनुरूप है, जिसके पहले ही वर्ष में 35 लाख सदस्य हो चुके हैं। यह प्रोग्राम सदस्यों को बिना किसी ब्लैकआउट तिथियों के इंडिगो की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में पॉइंट्स को आसानी से भुनाने की सुविधा देता है, जिससे लचीलापन और मूल्य अधिकतम होता है।

(ii) दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने रणनीतिक दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया: कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO अशोक वासवानी ने रोज़मर्रा की बैंकिंग को यादगार बनाते हुए, यादगार यात्रा के तालमेल पर प्रकाश डाला। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने बढ़ते वैश्विक नेटवर्क में ग्राहक निष्ठा बढ़ाने में ब्लूचिप की भूमिका पर ज़ोर दिया।

2. AIIB ने भारत में किफायती और हरित आवास के लिए IIFL होम फाइनेंस को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।



एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने हाल ही में भारत में किफायती और टिकाऊ आवास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFLHF) को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹835 करोड़) का ऋण देने का वादा किया है। इस ऋण का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए आवास ऋण की पहुँच का विस्तार करना और साथ ही भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हरित-प्रमाणित आवास को बढ़ावा देना है।

- यह निवेश मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय वर्ग (LIG) के लिए गृह ऋण की सुविधा को सक्षम बनाने पर केंद्रित है। IIFLHF द्वारा इस धनराशि का उपयोग घर बनाने या खरीदने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और किफायती आवास परियोजनाएँ बनाने वाले छोटे डेवलपर्स, दोनों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा, जो सामर्थ्य मानदंडों को पूरा करते हैं।

- यह सहयोग हरित आवास मानकों को अपनाने पर भी ज़ोर देता है, और IIFLHF का लक्ष्य IGBC (भारतीय हरित भवन परिषद) और GRIHA (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग) के तहत प्रमाणित घरों के अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। इससे भारत के कम कार्बन वाले आवास की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी और शहरी आवासों में दीर्घकालिक ऊर्जा खपत में कमी आएगी।

Key Points:-

(i) यह पहल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के उद्देश्यों और प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) जैसी केंद्रीय योजनाओं के अनुरूप है। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और ऋण-सीमित समुदायों को लक्षित करके, इसका उद्देश्य भारत के किराया आधारित आवास क्षेत्र में वित्तीय अंतर को पाटना और साथ ही सतत शहरी विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

(ii) IIFL होम फाइनेंस के कार्यकारी निदेशक और CEO मोनू रात्रा के अनुसार, AIIB के साथ यह साझेदारी जिम्मेदार ऋण और समावेशी आवास के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(iii) AIIB के महानिदेशक ग्रेगरी लियू ने भी कहा कि यह पहल भारत जैसे विकासशील सदस्य देशों के लिए समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश करने के AIIB के मुख्य मिशन का उदाहरण है।

फंड्स (PF) के लिए पाँच साल की कर छूट को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में स्थिर, दीर्घकालिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है।

● **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुलाई 2025 में अधिसूचना संख्या 113/2025 के माध्यम से लाभांश, ब्याज और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर लागू विस्तारित कर लाभ को औपचारिक रूप दिया। अब यह सुनिश्चित करता है कि धारा 50ए के तहत अल्पकालिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत गैर-सूचीबद्ध ऋण से प्राप्त LTCG भी कर-मुक्त रहेगा।**

Key Points:-

(i) 2020 में शुरू की गई यह छूट शुरू में मार्च 2024 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसे दो बार बढ़ाया गया है - पहले मार्च 2025 तक और अब मार्च 2030 तक। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF), सिंगापुर के GIC, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (CPPIB) और नॉर्वे के सॉवरेन पेंशन फंड जैसे वैश्विक निवेशकों सहित 35 से अधिक फंडों को लाभार्थी घोषित किया गया है।

(ii) यह नीति सड़क, बंदरगाह, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे जैसी प्रमुख परियोजनाओं को समर्थन देने की भारत की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। 2022 में, भारत में SWF और PF निवेश बढ़कर लगभग 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2021 में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था - जो कर स्थिरता के प्रति निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

(iii) वित्तीय विश्लेषक इस विस्तार को भारत के निवेश-अनुकूल रुख का एक स्पष्ट संकेत मानते हैं, जो बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित कर वातावरण का निर्माण करता है। यह न केवल दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में विश्वास बढ़ाता है, बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देकर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की

ECONOMY & BUSINESS

1. सरकार ने SWFs और पेंशन फंड के लिए कर छूट मार्च 2030 तक बढ़ा दी है।



भारत सरकार ने हाल ही में आयकर अधिनियम की धारा 10(23FE) के तहत बुनियादी ढाँचे में निवेश करने वाले सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWF) और पेंशन

भारत की महत्वाकांक्षा को भी बल देता है।

2. Nvidia वैश्विक स्तर पर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई।



जुलाई 2025 में, Nvidia Corporation, जो अमेरिका (USA) स्थित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और तेज़ कंप्यूटिंग की वैश्विक अग्रणी कंपनी है, दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई जिसने USD 4 ट्रिलियन (करीब ₹334 लाख करोड़) का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक AI हार्डवेयर प्रतिस्पर्धा में Nvidia की अग्रणी भूमिका को प्रमाणित करती है।

- Nvidia की यह ऐतिहासिक वृद्धि वैश्विक स्तर पर AI चिप्स की तेज़ मांग को दर्शाती है। कंपनी का मार्केट कैप जून 2023 में USD 1 ट्रिलियन, फरवरी 2024 में USD 2 ट्रिलियन, और जून 2024 में USD 3 ट्रिलियन रहा—और अब महज़ एक साल में USD 4 ट्रिलियन पार कर गया। यह वृद्धि AI क्षेत्र में Nvidia की तकनीकी लीडरशिप को मजबूत करती है।

- इस उपलब्धि के साथ, Nvidia ने Microsoft Corporation को पीछे छोड़ दिया, जिसका मौजूदा मार्केट कैप USD 3.75 ट्रिलियन है। Apple Inc. तीसरे स्थान पर है, जिसकी बाजार पूंजी USD 3.17 ट्रिलियन है। यह बदलाव दर्शाता है कि वैश्विक

तकनीकी फोकस पारंपरिक सॉफ्टवेयर से हटकर AI हार्डवेयर की ओर बढ़ चुका है।

Key Points:-

(i) Nvidia, चैटजीपीटी जैसे LLMs (बड़े भाषा मॉडल) को शक्ति प्रदान करने वाले बड़े डेटा केंद्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वैश्विक उन्नत AI सेमीकंडक्टर्स का लगभग 90% आपूर्ति करता है।

(ii) इसकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म (GCP) जैसे तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए आवश्यक हैं, जो अल्फाबेट इंक द्वारा संचालित हैं।

(iii) मार्च 2025 में, Nvidia ने अपने अत्याधुनिक Blackwell Ultra AI चिप्स लॉन्च किए, जो रियल-टाइम सोचने की क्षमता को तेज़ करते हैं, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को और अधिक ताकतवर बनाते हैं, और AI की सटीकता को सुधारते हैं। यह लॉन्च Nvidia को वैश्विक AI इन्फ्रास्ट्रक्चर के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करता है।

MOUs and Agreement

1. MeitY और BITS पिलानी ने सरकारी और उद्योग पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी राष्ट्रीय साइबर रक्षा एजेंसी CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) के माध्यम से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और निजी उद्योग के पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में आठ सप्ताह का व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

- 19 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम, बिट्स पिलानी, हैदराबाद परिसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (CRENS) में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रौद्योगिकी भागीदार रैपिड्रज का सहयोग और CERT-In का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह बिना किसी पूर्व कोडिंग अनुभव वाले पेशेवरों के लिए विशिष्ट रूप से खुला है, जो एक समावेशी, क्षमता-निर्माण डिज़ाइन को दर्शाता है।

- प्रतिभागियों को साइबर खतरों और कमजोरियों, नेटवर्क सुरक्षा (फ़ायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने/रोकथाम प्रणालियाँ, VPNs), सुरक्षित संचार और क्रिप्टोग्राफी, घटना प्रबंधन और फोरेंसिक के साथ-साथ क्लाउड सुरक्षा, मोबाइल खतरों और उन्नत सतत खतरों (APTs) पर उन्नत मॉड्यूल में विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। स्नातकों को CERT-इन और बिट्स पिलानी द्वारा संयुक्त रूप से जारी साइबर सुरक्षा में एक सह-ब्रांडेड व्यावसायिक विकास प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, जो शैक्षणिक कठोरता और राष्ट्रीय विश्वसनीयता का संयोजन प्रदान करेगा।

Key Points:-

(i) यह पहल पहली बार है जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के तहत नामित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी CERT-इन ने बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के साथ औपचारिक रूप से

साझेदारी की है।

(ii) CERT-In के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने कार्यक्रम को “एक जीवंत, उच्च कुशल प्रतिभा पूल बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया... जो उभरते डिजिटल और क्वांटम युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है”, जबकि बिट्स पिलानी के समूह कुलपति डॉ. वी. रामगोपाल राव ने कहा कि यह शिक्षा-उद्योग-सरकार सहयोग की ताकत का उदाहरण है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. वर्षा देशपांडे ने लैंगिक समानता के लिए 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता।



महाराष्ट्र के सतारा की महिला अधिकार कार्यकर्ता और दलित महिला विकास मंडल की सचिव वर्षा देशपांडे को हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

- यह प्रतिष्ठित सम्मान, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 11 जुलाई 2025 को चालीसवें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ और प्रजनन अधिकारों के लिए उनके 35 वर्षों के जमीनी स्तर के सक्रियता को स्वीकार करता है।

- 1990 में स्थापित उनके संगठन ने बाल विवाह, लिंग-भेदभावपूर्ण लिंग-चयन प्रथाओं और महिलाओं

के वित्तीय समावेशन को लक्षित करने वाली पहलों का बीड़ा उठाया है। लिंग-चयनात्मक गर्भपात क्लिनिकों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन, व्यावसायिक-कौशल प्रशिक्षण और संयुक्त संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा देने के माध्यम से, उनका काम ग्रामीण भारत में हाशिए पर पड़ी दलित महिलाओं को सशक्त बनाता है।

Key Points:-

(i) वर्षा ने सार्वजनिक नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निकायों की सदस्य के रूप में, उन्होंने लिंग-चयन को रोकने वाले कानूनों को लागू करने में मदद की और लिंग-भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर केंद्रित कानूनों पर सलाह दी।

(ii) पुरस्कार समारोह में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने UNFPA की कार्यकारी निदेशक डॉ. नतालिया कनम के माध्यम से उन्हें "परिवर्तन की ताकत" के रूप में याद किया, जिसमें सैकड़ों बाल विवाहों को रोकने, 10,000 से अधिक महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने और "लेक लड़की अभियान" (लड़कियों को संजोना) आंदोलन को बढ़ावा देने में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया।

(iii) वर्षा देशपांडे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्तियों - इंदिरा गांधी (1983) और JRD टाटा (1992) - के एक दुर्लभ समूह में शामिल हो गईं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ (IUSSP) ने इस वर्ष संस्थागत सम्मान जीता।

2. कुमार मंगलम बिड़ला भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए USISPF के निदेशक मंडल और कार्यकारी समिति में शामिल हुए।



जुलाई 2025 में, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष और प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (USISPF) के निदेशक मंडल और कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया। उनके शामिल होने का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बीच द्विपक्षीय विश्वास और आर्थिक सहयोग को गहरा करना है।

- कुमार मंगलम बिड़ला की नियुक्ति USISPF के मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय उद्योग भागीदारी के माध्यम से भारत-अमेरिका रणनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना है।

- उनके नेतृत्व से दोनों देशों के बीच नीति-स्तरीय सहभागिता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

- बिड़ला 1995 से आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स), पिलानी के कुलाधिपति हैं। वे IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और 2006 से 2013 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट प्रशासन पर सेबी समिति की अध्यक्षता भी की है।

Key Points:-

(i) कुमार मंगलम बिड़ला को व्यापार और उद्योग में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण (2023) सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।

(ii) अन्य पुरस्कारों में एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम (ABLF) ग्लोबल एशियन अवार्ड (2019), TIE ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड (2021), और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा ICAI हॉल ऑफ फेम अवार्ड (2024) शामिल हैं।

(iii) 2017 में स्थापित USISPF (संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच) वाणिज्यिक कूटनीति और निजी क्षेत्र की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाशिंगटन, डी.सी. में मुख्यालय वाला इसका उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नवाचार के माध्यम से दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मज़बूत, रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है।

SPORTS

1. हरिकृष्णन ए रा भारत के 87वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने।



जुलाई 2025 में, चेन्नई, तमिलनाडु के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए रा ने भारत के 87वें ग्रैंडमास्टर (GM) बनकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल

की। उन्होंने फ्रांस के प्रतिष्ठित ला प्लेग्रे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया, जिससे उन्होंने अपने कोच, ग्रैंडमास्टर श्याम सुंदर मोहनराज से किया वादा पूरा किया।

● हरिकृष्णन ने इससे पहले दो GM मानदंड अर्जित किए थे: पहला स्विट्जरलैंड में बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव (2023) में, और दूसरा स्पेन में लिस एंडुजार शतरंज ओपन (जून 2025) में। कई बार करीब पहुँचने के बाद, आखिरकार फ्रांस में उन्हें अपना लक्ष्य हासिल हुआ।

Key Points:-

(i) 2018 में इंटरनेशनल मास्टर (IM) से स्नातक करने के बाद, हरिकृष्णन का सफ़र सात साल लंबा रहा। उन्होंने अपने अंतिम मानदंड के साथ आवश्यक 2500 एलो रेटिंग सीमा पार कर ली, टूर्नामेंट में 5.5/9 अंक हासिल किए और 16 एलो अंक अर्जित किए।

(ii) चेन्नई स्थित शतरंज थुलिर अकादमी में जीएम श्याम सुंदर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित हरिकृष्णन ने असाधारण दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। लगातार नौ यूरोपीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए जाने जाने वाले, उनका लक्ष्य 2600+ एलो रेटिंग हासिल करना है और वे अमेरिका में एमबीए करने की योजना बना रहे हैं।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया।



वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 11 जुलाई 2025 को सी. सुब्रमण्यम सभागार, ICAR-NASC, पूसा परिसर, नई दिल्ली में आयोजित व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अंतर्गत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (CRCL) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में व्यापार, विज्ञान और नियामक क्षेत्रों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

● "निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता" विषय पर आयोजित इस पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के परीक्षण ढाँचे का आधुनिकीकरण करना था ताकि मंजूरी का समय कम हो, गुणवत्ता बनी रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। राज्य मंत्री चौधरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यापार को आसान बनाने के लिए आधुनिक, विज्ञान-आधारित प्रयोगशाला प्रणालियाँ आवश्यक हैं।

Key Points:-

(i) उद्घाटन सत्र के दौरान, कई प्रमुख प्रकाशन और सामग्री का विमोचन किया गया, जिनमें "सीमा पर विज्ञान: भारतीय सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं की कहानी" नामक एक वृत्तचित्र, सीआरसीएल की एक कॉफ़ी टेबल बुक, प्रयोगशाला की क्षमताओं का विवरण देने वाला एक ब्रोशर और पेट्रोलियम द्रव नमूने पर एक मानक संचालन प्रक्रिया वीडियो शामिल थे। इन विमोचनों ने 1912 में अपनी स्थापना के बाद

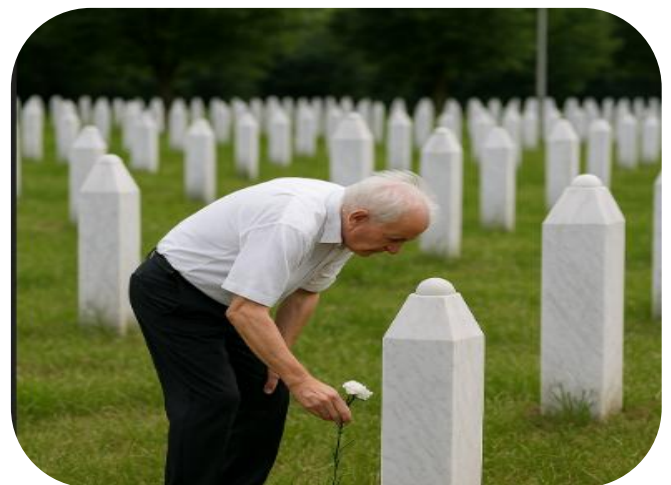
से सीआरसीएल की विकसित होती भूमिका पर प्रकाश डाला।

(ii) सम्मेलन में राजस्व प्रयोगशाला निदेशक वी. सुरेश सहित कई अधिकारियों और एफएसएसआई, सीडीएससीओ, वस्त्र समिति और पशु एवं पादप संगरोध जैसी सहयोगी सरकारी एजेंसियों (PGAs) के प्रतिनिधियों द्वारा तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया। चर्चाएँ व्यापार अनुपालन, एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्किंग, अनुसंधान एवं विकास, क्षमता निर्माण और प्रक्रिया सुधार पर केंद्रित रहीं।

(iii) प्रमुख परिणामों में परीक्षण समय को कम करने, देश भर में प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने, एक प्रमुख हितधारक समूह बनाने और प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धताएँ शामिल थीं। ये उपाय तेज़, सुरक्षित और अनुपालन योग्य निर्यात-आयात प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके भारत को एक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप हैं।

IMPORTANT DAYS

1. स्नेहेनिका में 1995 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन एवं स्मरण दिवस 2025, 11 जुलाई को मनाया गया।



स्रेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 जुलाई 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया, जो सामूहिक अत्याचार की 30वीं वर्षगांठ थी।

● यह दिन 8,300 से अधिक बोस्नियाई मुस्लिम (बोस्नियाक) पुरुषों और लड़कों की स्मृति का सम्मान करता है, जिन्हें बोस्नियाई युद्ध (1992-1995) के दौरान बोस्निया और हर्जेगोविना के स्रेब्रेनिका और उसके आसपास बोस्नियाई सर्व सेना द्वारा व्यवस्थित रूप से मार दिया गया था।

Key Points:-

(i) मई 2024 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संकल्प A/RES/78/282 को अपनाया, जिसके तहत 11 जुलाई को आधिकारिक तौर पर स्रेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के प्रति वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय चिंतन एवं स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया ताकि पीड़ितों को सम्मानित किया जा सके और नरसंहार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

(ii) यह प्रस्ताव जर्मनी और रवांडा द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 40 से अधिक देशों ने सह-प्रायोजक के रूप में इसका समर्थन किया था, जिसका उद्देश्य सामूहिक अत्याचारों के विरुद्ध वैश्विक स्मरण प्रयासों और निवारक कार्रवाई को मज़बूत करना था।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला आधिकारिक आयोजन 11 जुलाई 2024 को हुआ, जिसने इसे पीड़ितों और बचे लोगों के साथ ऐतिहासिक जवाबदेही और वैश्विक एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत एक वार्षिक स्मरणोत्सव के रूप में स्थापित किया।

Static GK

UNESCO	महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले	मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
Ministry of Tribal Affairs (MoTA)	मंत्री: श्री जुएल ओराम	मुख्यालय: नई दिल्ली
Kerala	मुख्यमंत्री: पिनारई विजयन	राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
the World Travel and Tourism Council (WTTC)	अध्यक्ष एवं CEO : जूलिया सिम्पसन	मुख्यालय : लंदन (UK)
Forbes	मुख्य कार्यकारी अधिकारी : शेरी फिलिप्स	मुख्यालय : न्यू जर्सी, USA
Nvidia	CEO : जेन्सेन हुआंग	मुख्यालय: सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
United States- India Strategic Partnership Forum (USISPF)	अध्यक्ष : जॉन टी. चेम्बर्स	मुख्यालय : वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)